भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्नल संख्या **858**

जिसका उत्तार शुक्रवार , 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।

संशोधित एनपीएस-।।। के तहत न्यूहनतम नियत लागत प्रावधान

858. श्री पर षोत्तनमभाई रुपाला:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2 अप्रैल, 2014 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू, संशोधित एनपीएस-।।। के तहत न्यूदनतम नियत लागत प्रावधानों को बहाल करने के लिए , उर्वरक विभाग ने व्याय विभाग के परामर्श से कुछ उर्वरक इकाइयों, जो मौजूदा नीति में निर्दिष्टन आर्थिक लाभों को नहीं जा सकी हैं , को ध्यायन में रखते हुए आज तक क्या कदम उठाए हैं और

(ख) सरकार 2 अप्रैल, 2014 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू मौजूदा नीति में निर्दिष्टछ आर्थिक लाभों को नहीं पा सकने वाली ऐसी उर्वरक इकाइयों की समस्या4 का समाधान कब तक करना चाहती है?

उत्तीर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्या मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख): उर्वरक विभाग ने मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए 2 अप्रैल 2014 को संशोधित एनपीएस-III जारी की, जिसमें सभी इकाइयों को 350 रुपए प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त नियत लागत का भुगतान; 30 वर्ष पूर्ण कर चुके और गैस में परिवर्तित यूरिया संयंत्रों को 150 रुपए प्रति मीट्रिक टन के विशेष प्रतिफल; और 2300 रुपए प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत या वर्ष 2012-13 के दौरान प्रचलित वास्तविक नियत लागत , जो भी कम हो , का भुगतान शामिल है। हालाँकि, दिनांक 30.03.2020 की अधिसूचना के तहत , संशोधित एनपीएस-III से 2300 रुपए प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत का प्रावधान हटा दिया गया था, जबकि संशोधित एनपीएस-III के बाकी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की इस टिप्पणी के अनुसार कि यूरिया इकाइयों की लागत से संबंधित मामलों को जांच और सिफारिश के लिए वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार (लागत) को भेजा जा सकता है, उर्वरक विभाग ने व्यय विभाग से अनुरोध किया कि मुख्य सलाहकार (लागत) संशोधित एनपीएस-III के तहत 2300 रुपए प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत के प्रावधानों को भूतलक्षी प्रभाव अर्थात 2 अप्रैल 2014 से बहाल करने के संबंध में जांच करें और अपनी सिफारिशें दें। मामले की जांच की जा रही है।

******